

Babru son of Chet **Bam**, resident of Balouti v. Basakha Singh **269**
son of Chet Ram, resident of Balouti Bhoh, and others
(M. L. Koul, J.)

माननीय एम. एल. कौल, जे.

बाबरू s/o चेत राम, r/o बलौती- याचिकाकर्ता

बनाम

बासखा सिंह s/o चेत राम, r/o बलौती भो और अन्य- प्रतिवादी

रेगुलर सेकंड अपील सं. 1448/79

19 मई, 1995

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1986- प्रथागत उत्तराधिकार का उन्मूलन-हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित उत्तराधिकार-संयुक्त परिवार की संपत्ति-ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकार।

अभिनिर्णीत किया गया कि धारा 4 के आधार पर पंजाब कृषि प्रथा जहां तक उत्तराधिकार के मामलों में हिंदूओं पर लागू थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई है और अब उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित सभी हिंदू संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में प्रथागत कानून के नियमों द्वारा शासित नहीं हैं।
(पैरा 8)

इसके अलावा, यह अभिनिर्णीत किया गया कि एक मिताक्षर सह-प्रतिलिपि में संपत्ति में मृतक का पुनर्भुगतान सह-कुल के जीवित सदस्यों को उत्तरजीवीता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार।
(पैरा 8)

एल. एन. वर्मा, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा,

निर्णय

एम. एल. कौल, जे.

(1) 16 जून, 1970 को अपने पिता चेत राम द्वारा निष्पादित एक पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलकर्ता बाबरू (जिसे इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में संदर्भित किया गया है) के पास गाँव भोज मातौर तहसील नारायणगढ़ में स्थित 230 बीघा और 19 बिस्वा भूमि का स्वामित्व है, जिनकी मृत्यु 18 दिसंबर, 1972 को हुई थी।

(2) उक्त प्रतिवादी नं. 1 और उसकी मां मुनी देवी प्रतिवादी नं. 2 (चेत राम की विधवा) के खिलाफ, बसखा सिंह और अन्य लोगों (जिसे इसके बाद वादी के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला के न्यायालय में अधिकार के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विचाराधीन संपत्ति पैतृक थी और यह संपत्ति प्रतिवादी नं. 1 के पिता को उनके सामान्य उत्तराधिकारी भगवान सिंह को हस्तांतरित कर दी गई थी, जो मृतक चेत राम के पिता थे। इसलिए, वादी और प्रतिवादी मुकदमाकारों के बीच प्रचलित प्रथा के अनुसार मालिक के रूप में उक्त पैतृक सम्पत्ति के हकदार थे और कथित चेत राम वादी को एक वसीयत के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 के मुकदमा में हित पैदा नहीं कर सकते थे ताकि उत्तराधिकार के रूप में उनके शेयरों के अनुसार प्रतिवादी के मुकदमा में प्रश्रुत संपत्ति प्राप्त की जा सके। वसीयत को प्रथा के खिलाफ होने के कारण चुनौती दी गई थी और इसलिए, क्योंकि वसीयत को उनके हित के खिलाफ अमान्य माना गया था, इसलिए निचली अदालत के समक्ष कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। इसके बाद, मामले की सुनवाई के दौरान, यह पाया गया कि विचाराधीन भूमि वास्तव में 230 बीघा और 19 बिस्वा नहीं थी, बल्कि यह केवल 119 बीघा और 1 बिस्वा थी और संपत्ति की ऐसी तथ्यात्मक स्थिति पक्षकारों द्वारा विवादित नहीं थी। इसलिए प्रतिवादियों संख्या 1 और 2 के खिलाफ वादी के पक्ष में निचली अदालत द्वारा शेयरों के अनुसार कब्जे के लिए एक डिक्री पारित की गई थी। हालाँकि, अभियोक्ता संख्या 2, 3 और 7 के मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने प्रतिअभियोक्ता संख्या 1 के मुकदमा में समझौता किया था और संपत्ति में अपने हित को आत्मसमर्पण कर दिया था।

(3) मामले की सुनवाई पर; यह पाया गया कि वसीयत exhibit P1 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित किया गया था, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त चेत राम पंजाब प्रथागत कानून द्वारा शासित संपत्ति का एक हिंदू पुरुष धारक होने के नाते, वसीयत द्वारा अपनी पैतृक अचल संपत्ति का निपटान करने के लिए स्वतंत्र नहीं था और उसके अनुयायियों को उक्त वसीयत को चुनौती देने का अधिकार था, जो कानून के खिलाफ था। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि वसीयत, वादी पर बाध्यकारी नहीं थी।

Babru son of Chet **Bam**, resident of Balouti v. Basakha Singh 271
son of Chet Ram, resident of Balouti Bhoh, and others
(M. L. Koul, J.)

(4) संपत्ति के पैतृक होने के संबंध में कोई विवाद नहीं था क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि इसमें शामिल कुछ संपत्ति चेत राम या प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा स्व-निर्मित थी। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि इतनी मिश्रित थी कि यह पता नहीं लगाया जा सका कि विवादित भूमि के कौन से हिस्से पैतृक थे और कौन से गैर-पैतृक थे। एक बार जब भूमि के पैतृक और गैर-पैतृक भागों को अलग नहीं किया जा सकता, तो उन्हें गैर-पैतृक माना जाना चाहिए। इस संबंध में, उनके तर्क को मजबूत करने के लिए, मारा और अन्य बनाम एम. एस. टी. *निखो* उपनाम पंजाब कौर और अन्य (1) मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अब पंजाब में यह लगातार शासन किया गया है कि जहां भूमि इतनी मिश्रित है कि पैतृक और गैर-पैतृक भागों को अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हें गैर-पैतृक माना जाना चाहिए जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि कौन से पैतृक हैं और कौन से नहीं हैं।"

(5) तत्काल मामले में, यह दिखाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने भूमि के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है जो प्रकृति में गैर-पैतृक हैं और उनके कब्जे में पूरी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चेत राम द्वारा निष्पादित वसीयत के माध्यम से उन्हें हस्तांतरित नहीं की गई है। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि विचाराधीन भूमि पैतृक थी और समेकन या अन्यथा संख्या में परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि भूमि के कुछ हिस्से गैर-पैतृक थे जो पैतृक सम्पत्ति के साथ मिश्रित हो गए थे और इसलिए, पूरी भूमि को प्रकृति में गैर-पैतृक घोषित किया जा सकता है। अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क, किसी भी तरह से, न्यायालय के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करता है, पहला इस तथ्य के लिए कि मामले की परिस्थितियों में, शीर्ष न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ता है और दूसरा, यह समवर्ती रूप से पाया जाता है कि विवाद में विषय वस्तु पूरी तरह से पैतृक भूमि पाई जाती है और किसी भी तरह से, कोई भी यह नहीं पा सकता है कि भूमि के कुछ हिस्से गैर-पैतृक थे और इस तरह से पूरी भूमि को गैर-पैतृक माना जाना चाहिए क्योंकि अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रकृति में पैतृक है।

(1) ए. आई. आर., 1964 एस. सी. 1821

(6) प्रतिवादी नंबर 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 2 और 4 के आधार पर पंजाब कृषि प्रथा, जहाँ तक यह हिंदुओं पर लागू था, अब उत्तराधिकार के मामलों के संबंध में लागू नहीं है, जो अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विचाराधीन संपत्ति, संपत्ति के अंतिम धारक चेत राम द्वारा वसीयत के निष्पादन द्वारा प्रतिवादी को हस्तांतरित कर दी गई है। कथित चेत राम की मृत्यु उसके द्वारा वसीयत की गई संपत्ति के संबंध में निर्वसीयत के रूप में नहीं हुई थी क्योंकि उसने एक वसीयत बनायी थी जो कानून के तहत प्रभावी होने में सक्षम था, जिसके आधार पर विचाराधीन संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 को एक मालिक के रूप में हस्तांतरित की गई थी।

(7) इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित प्रथा के नियम को समाप्त कर देती है और इसलिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद, किसी भी हिंदू को प्रथागत कानून के नियमों द्वारा शासित नहीं किया जा सकता है और किसी हिंदू द्वारा धारण की गई संपत्ति के उत्तराधिकार को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, उत्तराधिकार, अधिनियम के लागू होने के बाद खोला गया है और उत्तराधिकार के संबंध में पक्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित हैं और इस तरह विचाराधीन वसीयत उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होगी, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या उत्तराधिकार के उद्देश्यों के लिए विचाराधीन भूमि भी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आती है। हमें उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 और 6 को अलग-अलग नहीं पढ़ना है, बल्कि इन्हें एक-दूसरे के पूरक के रूप में एक साथ पढ़ना है।

(8) धारा 4 के आधार पर, पंजाब कृषि प्रथा जहाँ तक उत्तराधिकार के मामलों में हिंदुओं पर लागू थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई है और अब उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 2 में परिभाषित सभी हिंदू संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में प्रथागत कानून के नियमों द्वारा शासित नहीं हैं। इसलिए, कानूनी स्थिति यह सामने आती है कि उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद, अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित

Babru son of Chet **Bam**, resident of Balouti v. Basakha Singh **273**
son of Chet Ram, resident of Balouti Bhoj, and others
(M. L. Koul, J.)

सभी हिंदू उत्तराधिकार के मामलों के संबंध में हिंदू कानून और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों दोनों द्वारा शासित होते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने संयुक्त हिंदू परिवार और संयुक्त हिंदू **परिवार** संपत्ति की अवधारणा को किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया है। यह अधिनियम, किसी भी तरह से, उन लोगों के विशेष अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है जो मिताक्षर सह-अधिवेशन के सदस्य हैं, सिवाय अधिनियम की **धारा 6** और 30 में उल्लिखित तरीके और सीमा के। अधिनियम **के लागू** होने के बाद, हिंदू जो पहले अन्य हिंदुओं की तरह उत्तराधिकार के मामलों में प्रथागत कानून के नियमों द्वारा शासित थे, संयुक्त अविभाजित हिंदू परिवार का गठन करते हैं जिसमें मिताक्षर सह-सदस्य और संयुक्त सह-आंशिक संपत्ति के धारक के बेटे, **पोते** और परपोते शामिल हैं,

कुछ समय के लिए, जन्म से उसमें अधिकार प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 6 और 30 को बारीकी से पढ़ने पर, इन दो धाराओं के तहत कानून के अधिदेश में सहानुभूतिपूर्वक यह परिकल्पना की गई प्रतीत होती है कि जब कोई भी पुरुष हिंदू जो मर जाता है, इस अधिनियम के प्रारंभ में बदलाव करता है, तो उसकी मृत्यु के समय, एक मिताक्षर सह-स्थायी संपत्ति में अधिकार होने पर, संपत्ति में उसका हित सह-स्थायी के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि इस अधिनियम के अनुसार। यह इंगित करता है कि कोई भी हिंदू वसीयत या अन्य वसीयती स्वभाव से किसी भी संपत्ति का निपटान कर सकता है, जो पूरी तरह से उससे संबंधित है और पैतृक नहीं है। एक बार जब उक्त संपत्ति किसी पूर्वज से उसे हस्तांतरित हो जाती है, तो वह किसी भी तरह से उस संपत्ति का निपटान वसीयतनामा के माध्यम से नहीं कर सकता है, क्योंकि उक्त पैतृक सम्पत्ति में उसके हित के लिए उसके जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, सह-सदस्यता और इस अधिनियम के अनुसार नहीं। प्रीतम सिंह बनाम सहायक नियंत्रक, एस्टेट ड्यूटी, पटियाला (2) मामले में इस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले से मैं अपने विचार में मजबूत महसूस करता हूँ। इस विषय पर कानून की एक व्यापक व्याख्या यह दर्शाती है कि हालांकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 जहां तक उत्तराधिकार का संबंध है, प्रथा के नियम को समाप्त करती है लेकिन किसी भी तरह से, पैतृक सम्पत्ति के अंतिम धारक को वसीयती स्वभाव से सह-संसदीय के किसी भी जीवित सदस्य के पक्ष में अधिकार पैदा करने का हक नहीं देती है, जब तक कि इस तरह से वसीयत की गई संपत्ति किसी पुरुष हिंदू द्वारा स्व-निर्मित न हो या उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित संयुक्त, हिंदू परिवार के सदस्य के रूप में उत्तराधिकार के बावजूद उसके स्वामित्व में न आ जाए। इसी तरह कौर सिंह बनाम जगर सिंह (3) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पंजाब प्रथागत कानून द्वारा शासित एक पुरुष स्वामी को अपनी गैर-पैतृक सम्पत्ति पर निपटान की आत्यन्तिक शक्तियां हैं, लेकिन पैतृक सम्पत्ति का निपटान केवल आवश्यकता के लिए या अच्छे प्रबंधन के कार्य के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, कानून का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं उठाया गया था या इस बात पर विचार करने के लिए विचार नहीं किया गया था कि सामान्य पूर्वज मृतक चेत राम के पास कुछ गैर-पैतृक संपत्ति थी जिसे उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वसीयत किया था या उनके द्वारा पैतृक होने के कारण इस तरह से रखी गई संपत्ति का निपटान आवश्यकता से या अच्छे प्रबंधन के कार्य के लिए किया गया था। यह स्पष्ट किया गया है कि पैतृक सम्पत्ति वह संपत्ति है जो सामान्य पूर्वज के पास होती है और वंश द्वारा उसके उत्तराधिकारियों के पास आती है, और अन्य सभी संपत्ति गैर-पैतृक हैं। दोनों अदालतों का एक समवर्ती निष्कर्ष है कि विचाराधीन संपत्ति पैतृक है और जमाबंदी 68 में चेत मान द्वारा आयोजित संपत्ति के संबंध में कुछ परिवर्तन और क्षेत्र संख्याएँ, 69, जमाबंदी 87 और 88 में किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि कुछ संख्याएँ गैर-पैतृक थीं। यह नीचे दोनों अदालतों द्वारा समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया जाता है कि संपत्ति पैतृक

Babru son of Chet **Bam**, resident of Balouti v. Basakha Singh 275
son of Chet Ram, resident of Balouti Bhoh, and others
(M. L. Koul, J.)

थी जो प्रतिवादी संख्या 1 को किसी भी तरह से या वसीयत द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। इस तरह निचली अदालतों का मानना की वसीयत द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तांतरित नहीं की जा सकी संपत्ति को बरकरार रखा जाता है, हालांकि इस न्यायालय द्वारा ऊपर दिए गए विभिन्न कारणों से, *वसीयत को* आरम्भतः ही अमान्य माना जाता है। यह, किसी भी तरह से, वादी पर विचाराधीन संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में उत्तराधिकार के तरीके को प्रभावित नहीं करता है। प्रतिवादी नं. के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बढ़ाया गया अमान्य तर्क कि महिला वादी; अधिकार के लिए मुकदमा करने के हकदार नहीं थे पुरुष वारिस की उपस्थिति में, इस तथ्य के लिए कोई लाभ नहीं है कि ट्रायल न्यायालय और प्रथम अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भूमि की उत्पत्ति जो सामान्य पूर्वज से हुई है, हिन्दू, विधि और उत्तराधिकार अधिनियम उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है।

(2) 1976 पी. एल. आर. 343

(3) ए. आई. आर. 1961 पी. बी. 489.

इसलिए इस तर्क का कोई महत्व नहीं है और इसका अस्तित्व ही नहीं है। इस आधार पर कि एक प्रत्यावर्ती मुकदमा करने के लिए सक्षम है: पैतृक सम्पत्ति के संबंध में, जो *अंतिम* अधिकार के वसीयती स्वभाव के अनुसार पूर्वजों को हस्तांतरित की गई है –

(9) अतः सेकंड अपील विफल हो जाती है और इसको बर्खास्त कर दिया जाता है। हालांकि यह पाया गया है कि ट्रायल न्यायालय ने शेरों को ठीक से तय नहीं किया गया है-कानून के अनुसार, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी no 1 विचारण न्यायालय के समक्ष इस बिंदु पर आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, जो यह देखेगा कि डिग्री को ठीक किया गया है और पक्षकारों के उत्तराधिकार के शासन के कानून के अनुसार, शेरों में हिस्सेदारी के रूप में निष्पादित किया गया है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा